



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 03 सितम्बर, 2022 ई० (भाद्रपद 12, 1944 शक संवत्) [संख्या 36

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	759—763	3075	भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश		975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	723—745	1500	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975	भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	169—186	975	भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
			भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
			भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	431—436	975
			भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	..	1425
			स्टोर्स-पर्वेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-4

18 जुलाई, 2022 ई०

सं० 326/दो-4-2022-26/2(5)/2011-उप निबन्धक(Admin Misc.-1)/संयुक्त निबन्धक Admin (A-1 & A-4), मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई एल०एल०एम० डिग्री/उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनात स्थल (सर्वश्री/श्रीमति/सुश्री)	उप निबन्धक (एम०)/संयुक्त निबन्धक (एडमिन-1) मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/ उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
1	श्री चंदन कुमार सिंह, तत्कालीन सिविल जज (जू०डि०), नजीबाबाद-बिजनौर सम्प्रति सिविल जज (सी०डी०), बांसगाँव-गोरखपुर।	6151/IV-4340/ Admin.(A-1) दिनांक 16.05.2022	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।	एल०एल०एम०	2016
2	श्री नवनीत कुमार सिंह, अपर एडीशनल सिविल जज (जू०डि०), सिद्धार्थनगर।	6900 IV-5077/ Admin.(A-1) दिनांक 27.05.2022	राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।	एल०एल०एम०	2019

आज्ञा से,
घनश्याम मिश्र,
विशेष सचिव।

अनुभाग-1

सेवानिवृत्ति

25 जुलाई, 2022 ई०

सं० 965/दो-1-2022-19/1(4)/2010-उप सचिव, उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.07.2022 को अपरान्ह में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे :-

1-श्री नरेन्द्र सिंह पटेल, आई०ए०एस० (एस०सी०एस०-2005), सचिव, रेशम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2-डा० अजय शंकर पाण्डेय, आई०ए०एस० (एस०सी०एस०-2005), आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी।

3-श्री दिनेश कुमार सिंह-II, आई०ए०एस० (एस०सी०एस०-2005), आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।

4-डा० अशोक चन्द्र, आई०ए०एस० (एस०सी०एस०-2009), विशेष सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
धनन्जय शुक्ला,
विशेष सचिव।

वित्त (लेखा परीक्षा)

अनुभाग-1

पदोन्नति

27 जुलाई, 2022 ई०

सं० 10-24099/41/2022-3-I/194923/2022-श्री राज्यपाल विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री पदम् जंग, संयुक्त मुख्या लेखा परीक्षा अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (वेतन बैंड-3, रू० 15,600-39,100, ग्रेड पे 7,600) को मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ०प्र० के चयन वर्ष 2021-22 की रिक्ति के सापेक्ष उपलब्ध पद पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 'क' (वेतन बैंड-4 रू० 37,400-67,000, ग्रेड पे 8,900) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

2-उक्त नव पदोन्नत अधिकारी द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

आज्ञा से,
समीर,
विशेष सचिव।

अनुभाग-2

निरस्तीकरण

26 जुलाई, 2022 ई०

सं० 10-25001(099)/7/2021-4-I/194745/2022-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज के आदेश संख्या-अधि०/2022/क-194 दिनांक 30.6.2022 एवं आदेश संख्या-अधि०/2022/क-200 दिनांक 30.06.2022 द्वारा क्रमशः श्री राकेश कुमार, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, चंदौली एवं श्री प्रेमचन्द्र, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, मैनपुरी के उनके नाम के सम्मुख निम्नलिखित स्तम्भ-3 में अंकित स्थान से स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर किये गये स्थानान्तरण को जनहित में सम्यक् विचारोपरान्त एतद्वारा निरस्त किया जाता है :-

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री राकेश कुमार, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, चंदौली	सहायक निदेशक, निदेशालय, प्रयागराज
2	श्री प्रेमचन्द्र, वरिष्ठ सहायक	कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, मैनपुरी	कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सोनभद्र।

आज्ञा से,
हरिश्चन्द्र,
विशेष सचिव।

आबकारी विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-आदेश

22 जुलाई, 2022 ई०

सं० 1487/ई-1/तेरह-22-1292676/21-श्री रमा शंकर गुप्त, सहायक आबकारी आयुक्त (अनिवार्य सेवानिवृत्ति) द्वारा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1528(4)ई-1/तेरह-2017-सी०एम०-19/2017, दिनांक 30 अगस्त, 2017 के विरुद्ध योजित निदेश याचिका संख्या-1248/2018 रमा शंकर गुप्त बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश दिनांक 08 जुलाई, 2021 निम्नवत् हैं—

"As the decision of compulsory retirement in the case of the petitioner too is based on the recommendation of the same Screening Committee, it would it apparently suffers from the same infirmities as observed by the Hon'ble Court in the case of Sunil Kumar Sonkar (Supra). In this background, the order of compulsory retirement of the petitioner Sri Rama Shanker Gupta too is not sustainable and deserves to be set aside.

ORDER

The Claim Petition is allowed. The impugned order of compulsory retirement dated 30-08-2017 is hereby quashed with the direction to the Opposite Party No. 1 to treat the petitioner as having been reinstated from the day he was compulsorily retired. He shall be entitled to all consequential service benefits of which he might have been deprived due to the impugned order. They may be provided to the petitioner within three months of service a certified copy of this order."

2-मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण के उक्त निर्णय दिनांक 08.07.2022 के अनुपालन में आबकारी आयुक्त, उ०प्र० से आख्या प्राप्त की गयी। तत्क्रम में आबकारी आयुक्त द्वारा पत्र दिनांक 24-09-2021 के माध्यम से आख्या उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि श्री रमाशंकर गुप्त, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी की जिला झाँसी की तैनाती अवधि के दौरान उनको शासन के आदेश संख्या-1528(4)ई-1/तेरह-2017-सी०एम०-19/2017, दिनांक 30-08-2017 के द्वारा इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया है। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सेवा में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 11-08-2017 को अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। श्री गुप्त की वार्षिक प्रविष्टियों एवं संगत अभिलेखों के दृष्टिगत उक्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री गुप्त को अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने की संस्तुति की गयी। स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के क्रम में श्री महामहिम राज्यपाल (सक्षम प्राधिकारी) के आदेश के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 30-08-2017 द्वारा श्री गुप्त को लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया है। अतः श्री गुप्त को अनिवार्य सेवानिवृत्त सम्बन्धी उपरिवर्णित शासन को आदेश दिनांक 30-08-2017 लोकहित में निर्गत किया गया है और इसे जारी करने के दौरान किसी विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया गया।

आबकारी आयुक्त द्वारा उक्त आख्या उपलब्ध कराते हुए निदेश याचिका संख्या-1248/2018 रमा शंकर गुप्त बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश 08-07-2021 के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में रिट याचिका योजित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया।

3-आबकारी आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में, शासन के पत्र संख्या-को०के०168/ई-1/तेरह-21-129276/21, दिनांक 13-10-2021 द्वारा, निदेश याचिका संख्या-1248/2018 रमा शंकर गुप्त बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08-07-2021 के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में रिट याचिका योजित करने के निर्देश आबकारी आयुक्त को दिये गये। तत्क्रम में राज्य की ओर से रिट याचिका संख्या-538(एस०बी०)/2022 योजित की गयी, जिसे मा० उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07-02-2022 द्वारा निरस्त कर दिया।

इसी मध्य, मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-07-2021 का अनुपालन न होने से क्षुब्ध होकर श्री रमा शंकर गुप्त द्वारा मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण के समक्ष अवमानना वाद संख्या-240/2021 योजित किया गया है।

4—प्रकरण में आबकारी आयुक्त की आख्या एवं मुख्य स्थायी अधिवक्ता, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ की विधिक राय दिनांक 05-04-2022 के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निदेश याचिका संख्या-1248/2018 रमा शंकर गुप्त बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश दिनांक 08-07-2021 के समादर में याची श्री रमा शंकर गुप्त को अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1528(4)ई-1/तेरह-2017-सी0एम0-19/2017, दिनांक 30-08-2017 को एतद्वारा निरस्त करते हुए श्री रमा शंकर गुप्त को सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर सेवा में पुनर्स्थापित करने तथा तदनुसार वेतन एवं भत्तों का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5—कृपया तत्क्रम में आकारी आयुक्त, उ0प्र0 मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण में योजित निदेश याचिका संख्या-1248/2018 रमा शंकर गुप्त बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश दिनांक 08-07-2021 के अनुपालन में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
संजय आर0 भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-3

पदोन्नति

28 जुलाई, 2022 ई0

सं0 49/2022/1468/23-3-2022-03(ई0एस0)/2022—उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता स्तर-2 (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव (ज्येष्ठता क्र0-1751) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियंता स्तर-1 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड पे रु0 10,000/- (पे मैट्रिक्स लेवल-14) में नियमित पदोन्नति करने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1—श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

2—श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव अग्रिम आदेशों तक पूर्व तैनाती पद के कार्यों का निष्पादन करते रहेंगे।

आज्ञा से,
प्रभुनाथ,
विशेष सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 03 सितम्बर, 2022 ई० (भाद्रपद 12, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय,

विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

25 अगस्त, 2022 ई०

प्रारूप-18

(नियम-20 का उपनियम (2))

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

उत्तर प्रदेश सरकार

सं० 372/आठ-वि०भू०अ०अ० (सं०सं०)/वाराणसी-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जनपद वाराणसी के सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर की राय है कि जनपद वाराणसी में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के एल०पी०जी० भराई संयंत्र निर्माण हेतु ग्राम इसरवार, परगना कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी में 2.378 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

1-सामाजिक समाघात निर्धारण एजेंसी M/s. Social Responsibility Asia (Sr Asia) 4CS-25, Ansal Plaza Mall, Sector Vaishali Ghaziabad, U.P. द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी जिसे समुचित सरकार द्वारा पत्र संख्या 1029/आठ-वि०भू०अ०अ० (सं०सं०) दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

2-भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहे हैं।

3-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं-

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
वाराणसी	राजातालाब	कसवार राजा	इसरवार	180	हेक्टेयर 1.35
				181	1.028
				योग...	<u>2.378</u>

5-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये मा0 राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

6-अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर, वाराणसी को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

7-अधिनियम की धारा-11 (4) के अंतर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर, वाराणसी के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारंभिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल-नक्शा कलेक्टर, वाराणसी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी, वाराणसी।

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE ACT, 2013]

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

NOTIFICATION

August 25, 2022

No. 372/VIII-S.L.A.O.(J.O.)—Varanasi—Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/ Collector for the purpose of construction of Hindustan Petroleum Corporation Limited, District-Varanasi L.P.G. Botting Plant. District-Varanasi is of the opinion that a total of 2.378 hectares of land is required in the Village-Isarwar, Pargana- Kaswar Raja, Tehsil- Rajatalab, District -Varanasi.

1. Social Impact Assessment study was carried out by M/s. Social Responsibility Asia (Sr Asia) 4CS-25, Ansal Plaza Mall, Sector Vaishali Ghaziabad, U.P. and it has submitted its recommendations to the Appropriate Government Agency which has approved the social impact assessment carried out through its Letter No. 1029@ VIII-S.L.A.O./141a01a0½ Dated 09-12-2021-

2. Due to land acquisition no family is being displaced in the said village.

3. Therefore, the Governor is pleased to accept and notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6
Varanasi	Rajatalab	Kaswar Raja	Isarwar	180	<i>Hectares</i> 1.35
				181	1.028
				Total...	2.378

4. The Hon'ble Governor is also pleased to authorize the Collector, District Varanasi for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon, conduct survey of land, take levels of any land, dig into the sub-soil and do all the Acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

5. Under section 15 of the Act, any person whose interest lies in the land in question may within a period of 60 days after the publication of this notification, make an objection on acquisition of land in the locality in writing to the Collector, Varanasi.

6. Under section 11(4) of the Act, no person without prior approval of the Collector, Varanasi shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/ purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed.

NOTE: A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the Office of the Collector, Varanasi.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Collector, Varanasi.

कार्यालय, जिलाधिकारी, लखनऊ

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार

अधिनियम, 2013 की धारा-19 की अधिसूचना

दिनांक 11 अगस्त, 2022 ई०

संख्या-2775/आठ-अ०जि०अ०(भू०अ०)शा०सहा०परि० लखनऊ कमाण्डो ट्रेनिंग सेन्टर (ए०टी०एस०) उत्तर प्रदेश के विस्तारीकरण के लिए जनपद लखनऊ तहसील सरोजनीनगर के ग्राम बेहटवा की 15.4166 हे० व ग्राम अनौरा की 11.6670 हे० कुल 27.0836 हे० भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-2452/आठ-अ०जि०अ०(भू०अ०) शा०सहा० परि० लखनऊ दिनांक-16.08.2021 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक-24.08.2021 को प्रकाशित की गयी थी।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्रविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक-18.07.2022 पर विचारोपरान्त धारा 19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने के निर्देश देते हैं कि उन्हें समाधान हो गया है कि अनुसूची “क” में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है। तथा अनुसूची “ख” में उल्लिखित जिला लखनऊ तहसील सरोजनीनगर के सम्बन्धित ग्राम बेहटवा में 05 व ग्राम अनौरा में 02 कुल 07 विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के वर्णित भूमि का क्षेत्रफल व परिवारों का सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है। पुनर्वास प्रशासक/उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर की विस्थापन कार्ययोजना दिनांक-06.08.2022 में उल्लिखित किया गया है कि ग्राम बेहटवा के 05 परिवारों को गाटा संख्या-331 व ग्राम अनौरा के 02 परिवारों गाटा संख्या-39 में पुनर्वासित एवं पुनर्व्यवस्थापित किया जा सकेगा जो दोनों गाटे राजस्व अभिलेखों में ऊसर के नाम दर्ज है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्र0	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
01	लखनऊ	सरोजनीनगर	बेहटवा	64	4.475
02				72	0.013
03				77	0.089
04				79	0.177
05				80	0.506
06				82	0.013
07				84	0.063
08				85	0.038
09				86	0.051
10				88-क	0.266
11				93	0.146
12				94	0.152
13				99	0.101
14				101	0.190
15				102-क	0.086
16				102-ख	0.085
17				105-क	0.089
18				105-ख	0.099
19				106	0.182
20				108-क	0.063
21				108-ख	0.057
22				108-ग	0.164
23				108-घ	0.063
24				108-ङ	0.095
25				109	0.063
26				112	0.253
27				113	0.104

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
28	लखनऊ	सरोजनीनगर	बेहटवा	114	0.351
29				115	0.051
30				116-क	0.360
31				116-ख	0.107
32				117	0.108
33				118	0.136
34				119	0.101
35				120	0.177
36				121-क	0.025
37				121-ख	0.069
38				122	0.095
39				123	0.102
40				124	0.263
41				125	0.114
42				126	0.253
43				127	0.206
44				144	0.304
45				145-स	1.6475
46				146	0.051
47				150	0.164
48				152	0.164
49				154	0.114
50				155	0.872
51				156	1.620
52				162-स	0.1516
53				163-स	0.1275
				योग..	15.4166
01			अनौरा	714	0.219
02				715	0.122
03				716	0.127
04				717	0.347
05				718	0.922
06				719-सं0	0.506
07				720	0.107
08				721	0.038
09				722	0.050

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
10	लखनऊ	सरोजनीनगर	अनौरा	723	0.118
11				725	0.076
12				728	0.975
13				731	0.526
14				732	0.117
15				733-स	0.632
16				735-स	0.158
17				736	0.305
18				737-क	0.126
19				739-स	0.405
20				750	1.405
21				752	0.017
22				753	0.248
23				754	0.227
24				755	0.192
25				756	0.339
26				823	0.262
27				824	0.904
28				825	1.558
29				826	0.344
30				827	0.295
योग..					11.667
सकल योग..					27.0836

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
लखनऊ	सरोजनीनगर	बिजनौर	बेहटवा	131	0.0500
			अनौरा	39	0.0200

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ की इकाई शारदा सहायक परियोजना, कक्ष सं०-40, कलेक्ट्रेट, लखनऊ में देखा जा सकता है।

(सूर्य पाल गंगवार)
जिलाधिकारी,
लखनऊ।

कार्यालय, जिलाधिकारी मेरठ

(भूलेख अनुभाग)

20 जून, 2022

अधिसूचना

संख्या: 1272/सात- डी0एल0आर0सी0/2021- उप जिलाधिकारी, मेरठ की आख्या दिनांक 24-09-2021 में की गयी संस्तुति के क्रम में, शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 में प्रत्यायोजित उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा -77(2) एवं धारा 101 (2) के परन्तुक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के संरेखण में आ रही ग्राम अरनावली, तहसील व जिला मेरठ स्थित ग्राम समाज एवं डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के स्वामित्व की निम्न तालिका में अंकित भूमियों का श्रेणी परिवर्तन एवं विनिमय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता हूँ-

तालिका

ग्राम समाज की परियोजना के संरेखण में आ रही भूमियों का विवरण				डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 के स्वामित्व की विनियमय हेतु प्रस्तावित भूमि			
ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी	ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी
1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
आरनावली	144	0.0093	चकरोड	अरनावली	160	0.0170	1(क)
					161	0.0243	
					162	0.0090	
					163	0.0073	
					योग..	0.0576	
				दिलावरा	16	0.0033	
योग.. 01 किता		0.0093		कुल योग.. 05 किता		0.0609	

(1) ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है तथा इस हेतु श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य स्थितियों में किया जा रहा है। संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भूमियों पर यदि कोई जन शिकायत अथवा वाद लम्बित हो तो उसके निस्तारण पश्चात् ही भूमियों के विनिमय संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त विनिमय के पश्चात् ग्रामवासियों के सुविधाजनक आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

संख्या: 1273/सात- डी0एल0आर0सी0/2021- उप जिलाधिकारी, मेरठ की आख्या दिनांक 22-09-2021 में की गयी संस्तुति के क्रम में, शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 में प्रत्यायोजित उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा -77(2) एवं धारा 101 (2) के परन्तुक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के संरेखण में आ रही ग्राम सिंघावली, तहसील व जिला मेरठ स्थित ग्राम समाज एवं डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के

स्वामित्व की निम्न तालिका में अंकित भूमियों का श्रेणी परिवर्तन एवं विनिमय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता हूँ-

तालिका

ग्राम समाज की परियोजना के संरक्षण में आ रही भूमियों का विवरण				डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 के स्वामित्व की विनियमय हेतु प्रस्तावित भूमि			
ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी	ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी
1	2	3	4	1	2	3	4
सिंधावली	426	हेक्टेयर	चकमार्ग	सिंधावली	428	हेक्टेयर	
		0.0215				0.0153	
						0.0323	
	446	0.0143	चकमार्ग		449	0.0038	
						योग..	
0.0200							
योग..	0.0358			450	0.0063		
				योग..	0.0263		

(1) ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है तथा इस हेतु श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य स्थितियों में किया जा रहा है। संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भूमियों पर यदि कोई जन शिकायत अथवा वाद लम्बित हो तो उसके निस्तारण पश्चात् ही भूमियों के विनिमय संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त विनियम के पश्चात् ग्रामवासियों के सुविधाजनक आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

संख्या: 1274/सात- डी0एल0आर0सी0/2021- उप जिलाधिकारी, मेरठ की आख्या दिनांक 22-09-2021 में की गयी संस्तुती के क्रम में, शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 में प्रत्यायोजित उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा -77(2) एवं धारा 101 (2) के परन्तुक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के संरेखण में आ रही ग्राम पेपला, तहसील व जिला मेरठ स्थित ग्राम समाज एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के स्वामित्व की निम्न तालिका में अंकित भूमियों का श्रेणी परिवर्तन एवं विनिमय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता हूँ-

तालिका

ग्राम समाज की परियोजना के संरेखण में आ रही भूमियों का विवरण				डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 के स्वामित्व की विनियमय हेतु प्रस्तावित भूमि			
ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी	ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी
1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
पेपला	358	0.0156	चकमार्ग	पेपला	355	0.0270	1(क)

1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
पेपला	405	0.0220	चकमार्ग	पेपला	404	0.0160	1(क)
	489	0.0038	नाली		493	0.0045	
	349	0.0090	चकमार्ग		350	0.0224	
					351	0.0100	
					योग..	0.0324	
	347	0.0092	चकमार्ग		348	0.0292	
					97	0.0094	
					योग..	0.0386	
	334	0.0070	नाली		346-मि0	0.0365	

(1) ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है तथा इस हेतु श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य स्थितियों में किया जा रहा है। संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भूमियों पर यदि कोई जन शिकायत अथवा वाद लम्बित हो तो उसके निस्तारण पश्चात् ही भूमियों के विनिमय संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त विनिमय के पश्चात् ग्रामवासियों के सुविधाजनक आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

संख्या: 1275/सात- डी0एल0आर0सी0/2021-उप जिलाधिकारी, मेरठ की आख्या दिनांक 24-09-2021 में की गयी संस्तुति के क्रम में, शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में प्रत्यायोजित उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-77(2) एवं धारा 101 (2) के परन्तुक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के संरेखण में आ रही ग्राम घाट, तहसील व जिला मेरठ स्थित ग्राम समाज एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के स्वामित्व की निम्न तालिका में अंकित भूमियों का श्रेणी परिवर्तन एवं विनिमय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता हूँ-

तालिका

ग्राम समाज की परियोजना के संरेखण में आ रही भूमियों का विवरण				डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 के स्वामित्व की विनियमय हेतु प्रस्तावित भूमि			
ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी	ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी
1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
घाट	451	0.0220	चकमार्ग	घाट	450	0.0286	1(क)
					445	0.0226	
					योग..	0.0512	
	443	0.0115	चकमार्ग		441	0.0110	
					440	0.0200	

1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
घाट		चकमार्ग		घाट	433	0.0220	1(क)
					429	0.0080	
					योग..	0.0610	
	427	0.0190	चकमार्ग		424	0.0225	
					425	0.0150	
					योग..	0.0375	
	243	0.0090	चकमार्ग		236	0.0206	
					235	0.0230	
					योग..	0.0436	
	145	0.0093	चकमार्ग		142	0.0258	
					143	0.0065	
					147	0.0120	
					148	0.0105	
					योग..	0.0548	
	89	0.0038	चकमार्ग		77	0.0030	
	467	0.0150	चकमार्ग		468	0.0055	

(1) ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है तथा इस हेतु श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य स्थितियों में किया जा रहा है। संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भूमियों पर यदि कोई जन शिकायत अथवा वाद लम्बित हो तो उसके निस्तारण पश्चात् ही भूमियों के विनिमय संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त विनिमय के पश्चात् ग्रामवासियों के सुविधाजनक आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

संख्या: 1276/सात- डी0एल0आर0सी0/2021-उप जिलाधिकारी, मेरठ की आख्या दिनांक 22-09-2021 में की गयी संस्तुति के क्रम में, शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में प्रत्यायोजित उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-77(2) एवं धारा 101 (2) के परन्तुक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के संरक्षण में आ रही ग्राम छजमलपुर उर्फ छज्जूपुर, तहसील व जिला मेरठ स्थित ग्राम समाज एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के स्वामित्व की निम्न तालिका में अंकित भूमियों का श्रेणी परिवर्तन एवं विनिमय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता हूँ-

तालिका

ग्राम समाज की परियोजना के संरेखण में आ रही भूमियों का विवरण				डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 के स्वामित्व की विनियमय हेतु प्रस्तावित भूमि			
ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी	ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी
1	2	3	4	1	2	3	4
छजमलपुर उर्फ छज्जपुर	669	0.0128	नाली	छजमलपुर उर्फ छज्जपुर	690	हेक्टेयर	1(क)
						हेक्टेयर	
						0.0070	
						0.0088	
						0.0103	
						योग..	
						0.0261	
						0.0170	
						0.0175	
						योग..	
						0.0345	
	670	0.0253	चकमार्ग	छजमलपुर उर्फ छज्जपुर	690	0.0170	1(क)
						0.0175	
						योग..	
						0.0345	
						0.0180	
						योग..	
						0.0180	
						0.0004	
						0.0058	
						0.0108	
						योग..	
						0.0170	
	403	0.0055	चकमार्ग	छजमलपुर उर्फ छज्जपुर	400	0.0028	1(क)
						0.0115	
						0.0215	
						योग..	
						0.0358	
						0.0025	
						0.0040	
						0.0090	
						0.0080	
						0.0013	
						योग..	
						0.0248	
	352	0.0068	नाली	छजमलपुर उर्फ छज्जपुर	332	0.0258	1(क)
						योग..	
						0.0258	
						0.0325	
						0.0190	
						0.0138	
						योग	
						0.0653	
						कुल योग..	
						07 किता	
						0.1005	
	353	0.0128	चकमार्ग	उपलेहडा	314	0.0258	1(क)
						योग..	
						0.0258	
						0.0325	
						0.0190	
						0.0138	
						योग	
						0.0653	
						कुल योग..	
						21किता	
						0.2473	

(1) ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है तथा इस हेतु श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य स्थितियों में किया जा रहा है। संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भूमियों पर यदि कोई जन शिकायत अथवा वाद लम्बित हो तो उसके निस्तारण पश्चात् ही भूमियों के विनिमय संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त विनिमय के पश्चात् ग्रामवासियों के सुविधाजनक आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

संख्या: 1277/सात- डी०एल०आर०सी०/2021-उप जिलाधिकारी, मेरठ की आख्या दिनांक 22-09-2021 में की गयी संस्तुति के क्रम में, शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 में प्रत्यायोजित उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा-77(2) एवं धारा 101 (2) के परन्तुक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के संरेखण में आ रही ग्राम पांचली खुर्द, तहसील व जिला मेरठ स्थित ग्राम समाज एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के स्वामित्व की निम्न तालिका में अंकित भूमियों का श्रेणी परिवर्तन एवं विनिमय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता हूँ-

तालिका

ग्राम समाज की परियोजना के संरेखण में आ रही भूमियों का विवरण				डी०एफ०सी०सी०आई०एल० के स्वामित्व की विनियमय हेतु प्रस्तावित भूमि			
ग्राम का नाम	खसरा सं०	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी	ग्राम का नाम	खसरा सं०	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी
1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
पांचली खुर्द	18	0.0126	चकमार्ग	पांचली खुर्द	23	0.0040	1 (क)
					24	0.0298	
					50	0.0065	
					51	0.0151	
					52	0.0175	
					योग..	0.0729	
	845	0.0032	नाली		844	0.0047	
	863	0.0185	रास्ता		841	0.0106	
					843	0.0613	
					844	0.0106	
					योग..	0.0825	
कुल योग ..	03 किता	0.0343		कुल योग ..	09 किता	0.1601	

(1) ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है तथा इस हेतु श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य स्थितियों में किया जा रहा है। संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भूमियों पर यदि कोई जन शिकायत अथवा वाद लम्बित हो तो उसके निस्तारण पश्चात् ही भूमियों के विनिमय संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त विनिमय के पश्चात् ग्रामवासियों के सुविधाजनक आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

संख्या: 1278/सात- डी0एल0आर0सी0/2021- उप जिलाधिकारी, मेरठ की आख्या दिनांक 24-09-2021 में की गयी संस्तुति के क्रम में, शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 में प्रत्यायोजित उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-77(2) एवं धारा 101 (2) के परन्तुक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के संरेखण में आ रही ग्राम महरौली, तहसील व जिला मेरठ स्थित ग्राम समाज एवं डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के स्वामित्व की निम्न तालिका में अंकित भूमियों का श्रेणी परिवर्तन एवं विनिमय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता हूँ-

तालिका

ग्राम समाज की परियोजना के संरेखण में आ रही भूमियों का विवरण				डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 के स्वामित्व की विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि			
ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी	ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी
1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
महरौली	8	0.0700	रास्ता	महरौली	76	0.0162	1 (क)
					77/1	0.0416	1 (क)
					77/2	0.0068	1 (क)
					78	0.0253	1 (क)
					योग..	0.0899	

(1) ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है तथा इस हेतु श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य स्थितियों में किया जा रहा है। संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भूमियों पर यदि कोई जन शिकायत अथवा वाद लम्बित हो तो उसके निस्तारण पश्चात् ही भूमियों के विनिमय संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त विनिमय के पश्चात् ग्रामवासियों के सुविधाजनक आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

संख्या: 1279/सात- डी0एल0आर0सी0/2021-उप जिलाधिकारी, मेरठ की आख्या दिनांक 22-09-2021 में की गयी संस्तुति के क्रम में, शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 में प्रत्यायोजित उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-77(2) एवं धारा 101 (2) के परन्तुक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के संरेखण में आ रही ग्राम महीउद्दीनपुर, तहसील व जिला मेरठ स्थित ग्राम समाज एवं डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के स्वामित्व की निम्न तालिका में अंकित भूमियों का श्रेणी परिवर्तन एवं विनिमय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता हूँ-

तालिका

ग्राम समाज की परियोजना के संरेखण में आ रही भूमियों का विवरण				डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 के स्वामित्व की विनियमय हेतु प्रस्तावित भूमि			
ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी	ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी
1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
महीउद्दीनपुर	479	0.0245	चकमार्ग	महीउद्दीनपुर	480	0.0250	1 (क)

(1) ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है तथा इस हेतु श्रेणी परिवर्तन/विनियम अपरिहार्य स्थितियों में किया जा रहा है। संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भूमियों पर यदि कोई जन शिकायत अथवा वाद लम्बित हो तो उसके निस्तारण पश्चात् ही भूमियों के विनियम संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त विनियम के पश्चात् ग्रामवासियों के सुविधाजनक आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

संख्या: 1280/सात- डी0एल0आर0सी0/2021-उप जिलाधिकारी, मेरठ की आख्या दिनांक 22-09-2021 में की गयी संस्तुति के क्रम में, शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में प्रत्यायोजित उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-77(2) एवं धारा 101 (2) के परन्तुक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के संरेखण में आ रही ग्राम जंगेठी, तहसील व जिला मेरठ स्थित ग्राम समाज एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के स्वामित्व की निम्न तालिका में अंकित भूमियों का श्रेणी परिवर्तन एवं विनियम किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता हूँ-

तालिका

ग्राम समाज की परियोजना के संरेखण में आ रही भूमियों का विवरण				डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 के स्वामित्व की विनियमय हेतु प्रस्तावित भूमि			
ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी	ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी
1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
जंगेठी	502	0.0175	चकमार्ग	जंगेठी	500	0.0290	1(क)
	517	0.0150	चकमार्ग		505	0.0173	
					504	0.0148	
					योग..	0.0321	
	425	0.0070	चकमार्ग		409	0.0050	
					413	0.075	
					416	0.0175	

1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
जंगेटी			चकमार्ग	जंगेटी	417	0.0355	1(क)
					428	0.0115	
					योग..	0.1445	
	360	0.0230	चकमार्ग		108	0.0080	
					357	0.0180	
					382	0.0125	
					386	0.0200	
					योग..	0.0585	
	49	0.0153	चकमार्ग		89	0.0300	
					90	0.0140	
					91	0.0105	
					योग	0.2577	
कुल योग..	05 किता	0.0778			15 किता	0.2511	

(1) ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है तथा इस हेतु श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य स्थितियों में किया जा रहा है। संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भूमियों पर यदि कोई जन शिकायत अथवा वाद लम्बित हो तो उसके निस्तारण पश्चात् ही भूमियों के विनिमय संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त विनिमय के पश्चात् ग्रामवासियों के सुविधाजनक आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

संख्या: 1281/सात- डी0एल0आर0सी0/2021-उप जिलाधिकारी, मेरठ की आख्या दिनांक 22-09-2021 में की गयी संस्तुति के क्रम में, शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में प्रत्यायोजित उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-77(2) एवं धारा 101 (2) के परन्तुक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के संरक्षण में आ रही ग्राम बहादुरपुर, तहसील व जिला मेरठ स्थित ग्राम समाज एवं डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के स्वामित्व की निम्न तालिका में अंकित भूमियों का श्रेणी परिवर्तन एवं विनिमय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता हूँ-

तालिका

ग्राम समाज की परियोजना के संरेखण में आ रही भूमियों का विवरण				डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 के स्वामित्व की विनियमय हेतु प्रस्तावित भूमि			
ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी	ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी
1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
बहादुरपुर	183	0.0054	नाली	बहादुरपुर	181	0.0093	1(क)
	105	0.0098	चकमार्ग		106	0.0065	
	80/590	0.0150	चकमार्ग		107	0.0080	
					81	0.0053	
					80	0.0100	
योग..		0.0302		योग..		0.0391	

(1) ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है तथा इस हेतु श्रेणी परिवर्तन/विनियम अपरिहार्य स्थितियों में किया जा रहा है। संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भूमियों पर यदि कोई जन शिकायत अथवा वाद लम्बित हो तो उसके निस्तारण पश्चात् ही भूमियों के विनियम संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त विनियम के पश्चात् ग्रामवासियों के सुविधाजनक आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

संख्या: 1282/सात- डी0एल0आर0सी0/2021-उप जिलाधिकारी, सरधना की आख्या दिनांक 20-04-2022 में की गयी संस्तुति के क्रम में, शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में प्रत्यायोजित उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-77(2) एवं धारा 101 (2) के परन्तुक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के संरेखण में आ रही ग्राम मटौर तहसील व जिला मेरठ स्थित ग्राम समाज एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के स्वामित्व की निम्न तालिका में अंकित भूमियों का श्रेणी परिवर्तन एवं विनियम किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता हूँ-

तालिका

ग्राम समाज की परियोजना के संरेखण में आ रही भूमियों का विवरण				डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 के स्वामित्व की विनियमय हेतु प्रस्तावित भूमि			
ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी	ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी
1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
मटौर	384	0.0325	6-1 नाली	मटौर	382	0.0155	6(2)
					383	0.0082	6(2)
					407	0.0090	6(2)

1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
					406	0.0065	1(क)
					401	0.0085	1(क)
					396	0.0180	1(क)
					391	0.0065	6(2)
					390	0.0063	1(क)
					389	0.0040	6(2)
	315	0.0045	6-1नाली		341	0.0132	1(क)
					344	0.0125	6(2)
					335	0.0100	6(2)
	646	0.0045	6-1नाली		643	0.0098	6(2)
कुल योग..	03 किता	0.0415		कुल योग..	13 किता	0.1280	

(1) ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है तथा इस हेतु श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य स्थितियों में किया जा रहा है। संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भूमियों पर यदि कोई जन शिकायत अथवा वाद लम्बित हो तो उसके निस्तारण पश्चात् ही भूमियों के विनिमय संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त विनिमय के पश्चात् ग्रामवासियों के सुविधाजनक आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

संख्या: 1283/सात- डी0एल0आर0सी0/2021-उप जिलाधिकारी, सरधना की आख्या दिनांक 20-04-2022 के क्रम में, शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में प्रत्यायोजित उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-77(2) एवं धारा 101 (2) के परन्तुक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के संरेखण में आ रही ग्राम जसरथपुर, तहसील सरधना, जिला मेरठ स्थित ग्राम समाज एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के स्वामित्व की निम्न तालिका में अंकित भूमियों का श्रेणी परिवर्तन एवं विनिमय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता हूँ-

तालिका

ग्राम समाज की परियोजना के संरेखण में आ रही भूमियों का विवरण				डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 के स्वामित्व की विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि			
ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी	ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी
1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
जसरथपुर	250	0.2550	चकरोड	जसरथपुर	249	0.0120	1(क)
			6(2)		248	0.0104	

1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
					247	0.0195	
					246	0.0114	
					241	0.0546	
					239	0.0348	
					238	0.0330	
					236	0.0442	
					235	0.0333	
	229	0.0540	चकरोड 6(2)		230	0.0660	
कुल योग..	02 किता	0.3090		कुल योग..	10 किता	0.3192	

(1) ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है तथा इस हेतु श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य स्थितियों में किया जा रहा है। संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भूमियों पर यदि कोई जन शिकायत अथवा वाद लम्बित हो तो उसके निस्तारण पश्चात् ही भूमियों के विनिमय संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त विनिमय के पश्चात् ग्रामवासियों के सुविधाजनक आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

20 जून, 2022

अधिसूचना

संख्या: 1284/सात- डी0एल0आर0सी0/2021-उप जिलाधिकारी, सरधना की आख्या दिनांक 07-04-2022 के क्रम में, शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 में प्रत्यायोजित उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-77(2) एवं धारा 101 (2) के परन्तुक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के संरेखण में आ रही ग्राम पौहल्ली, तहसील सरधना जिला मेरठ स्थित ग्राम समाज एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के स्वामित्व की निम्न तालिका में अंकित भूमियों का श्रेणी परिवर्तन एवं विनिमय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता हूँ-

तालिका

ग्राम समाज की परियोजना के संरेखण में आ रही भूमियों का विवरण				डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 के स्वामित्व की विनियमय हेतु प्रस्तावित भूमि			
ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी	ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी
1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
पौहल्ली	1277	0.5365	हड़वार	पौहल्ली	1273	0.4365	1 (क)
					1272	0.1000	
					योग..	0.5365	

(1) ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है तथा इस हेतु श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य स्थितियों में किया जा रहा है। संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भूमियों पर यदि कोई जन शिकायत अथवा वाद लम्बित हो तो उसके निस्तारण पश्चात् ही भूमियों के विनिमय संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त विनिमय के पश्चात् ग्रामवासियों के सुविधाजनक आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

संख्या: 1285/सात- डी0एल0आर0सी0/2021-उप जिलाधिकारी, सरधना की आख्या दिनांक 07-04-2022 के क्रम में, शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में प्रत्यायोजित उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-77(2) एवं धारा 101 (2) के परन्तुक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना के संरेखण में आ रही ग्राम खिर्वा नौआबाद, तहसील सरधना, जिला मेरठ स्थित ग्राम समाज एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के स्वामित्व की निम्न तालिका में अंकित भूमियों का श्रेणी परिवर्तन एवं विनिमय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता हूँ-

तालिका

ग्राम समाज की परियोजना के संरेखण में आ रही भूमियों का विवरण				डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 के स्वामित्व की विनियमय हेतु प्रस्तावित भूमि			
ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी	ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी
1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
खिर्वा नौआबाद	177	0.0590	चकमार्ग	खिर्वा नौआबाद	180	0.0096	1(क)
					178	0.0068	
					176	0.0258	
					174	0.0025	
	175	0.0010	नाली		174	0.0015	1(क)
	244	0.0150	चकमार्ग		246	0.0285	1(क)
					248	0.0070	
					249	0.00225	
योग..	03किता	0.0750		योग..	08किता	0.1042	

(1) उक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य स्थितियों में किया जा रहा है। संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट की 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(2) प्रश्नगत भूमियों पर यदि कोई जन शिकायत अथवा वाद लम्बित हो तो उसके निस्तारण पश्चात् ही भूमियों के विनिमय संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त विनिमय के पश्चात् ग्रामवासियों के सुविधाजनक आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

संख्या: 1286/सात- डी0एल0आर0सी0/2021-उप जिलाधिकारी, सरधना की आख्या दिनांक 13-04-2022 के क्रम में, शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में प्रत्यायोजित उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-77(2) एवं धारा 101 (2) के परन्तुक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

परियोजना के संरेखण में आ रही ग्राम मछरी, तहसील सरधना जिला मेरठ स्थित ग्राम समाज एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के स्वामित्व की निम्न तालिका में अंकित भूमियों का श्रेणी परिवर्तन एवं विनियम किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता हूँ-

तालिका

ग्राम समाज की परियोजना के संरेखण में आ रही भूमियों का विवरण				डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 के स्वामित्व की विनियमय हेतु प्रस्तावित भूमि			
ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/ श्रेणी	ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी
1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
मछरी	1246	0.0100	6(2)चकमार्ग	मछरी	1248	0.0324	1(क)
					1245	0.0200	
	1253	0.0138	6(2)चकमार्ग		1254	0.0090	
					1255	0.0090	
					1256	0.0023	
	1236	0.0103	6(2)चकमार्ग		1231	0.0050	
					1232	0.0055	
					1235	0.0190	
	1230	0.0065	6(1) नाली		1231	0.0028	
					1232	0.0030	
					1235	0.0098	
	914	0.0124	6(1) नाली		909	0.0018	
					911	0.0068	
					913	0.0007	
					908	0.0040	
	916	0.0234	6(1) नाली		918	0.0008	
					920	0.0105	
					921	0.0095	
					922	0.0038	
					923	0.0190	
	917	0.0098	6(1) नाली		918	0.0070	
					920	0.0055	
					921	0.0050	
					922	0.0022	
					923	0.0098	

1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
मछरी	910	0.0075	6(2)चकमार्ग	मछरी	911	0.0140	
					913	0.0020	
	897	0.0050	6(2)चकमार्ग		908	0.0080	
					909	0.0090	
					903	0.0060	
					902	0.0085	
कुल योग..	09किता	0.0987		कुला योग..	31किता	0.2517	

(1) ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है तथा इस हेतु श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य स्थितियों में किया जा रहा है। संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भूमियों पर यदि कोई जन शिकायत अथवा वाद लम्बित हो तो उसके निस्तारण पश्चात् ही भूमियों के विनिमय संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त विनिमय के पश्चात् ग्रामवासियों के सुविधाजनक आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

संख्या: 1287/सात- डी0एल0आर0सी0/2021-उप जिलाधिकारी, सरधना की आख्या दिनांक 20-04-2022 के क्रम में, शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में प्रत्यायोजित उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-77(2) एवं धारा 101 (2) के परन्तुक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के संरेखण में आ रही ग्राम दौराला, तहसील सरधना, जिला मेरठ स्थित ग्राम समाज एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के स्वामित्व की निम्न तालिका में अंकित भूमियों का श्रेणी परिवर्तन एवं विनिमय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता हूँ-

तालिका

ग्राम समाज की परियोजना के संरेखण में आ रही भूमियों का विवरण				डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 के स्वामित्व की विनियमय हेतु प्रस्तावित भूमि			
ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी	ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी
1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
दौराला	237	0.0045	चकमार्ग	दौराला	240	0.0035	1(क)
	489	0.0008	नाली		291	0.0005	1(क)
	485	0.0163	चकमार्ग		491	0.0010	1(क)
					488	0.0240	
					179	0.0163	
	172	0.0120	चकमार्ग		194	0.0100	1(क)
					190	0.0078	
					167	0.0210	
	166	0.0315	चकमार्ग		152	0.0145	1(क)
	151	0.0073	चकमार्ग		150	0.0060	1(क)
					149	0.0233	
	188-ख	0.0141	नाली		194	0.00120	1(क)
					190	0.0096	
07किता		0.0865 हे0		13 किता		0.1495 हे0	

(1) ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है तथा इस हेतु श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य स्थितियों में किया जा रहा है। संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भूमियों पर यदि कोई जन शिकायत अथवा वाद लम्बित हो तो उसके निस्तारण पश्चात् ही भूमियों के विनिमय संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त विनिमय के पश्चात् ग्रामवासियों के सुविधाजनक आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

संख्या: 1288/सात- डी०एल०आर०सी०/2021-उप जिलाधिकारी, सरधना की आख्या दिनांक 20-04-2022 के क्रम में, शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में प्रत्यायोजित उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा-77(2) एवं धारा 101 (2) के परन्तुक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के संरेखण में आ रही ग्राम कनौड़ा, तहसील सरधना, जिला मेरठ स्थित ग्राम समाज एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के स्वामित्व की निम्न तालिका में अंकित भूमियों का श्रेणी परिवर्तन एवं विनिमय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता हूँ-

तालिका

ग्राम समाज की परियोजना के संरेखण में आ रही भूमियों का विवरण				डी०एफ०सी०सी०आई०एल० के स्वामित्व की विनियमय हेतु प्रस्तावित भूमि			
ग्राम का नाम	खसरा सं०	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी	ग्राम का नाम	खसरा सं०	क्षेत्रफल	प्रकृति/श्रेणी
1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
कनौड़ा	279	0.1474	पशुचर 5(3) ग	कनौड़ा	53	0.1474	1(क)
	264	0.3170	6(2) चकमार्ग		242	0.0060	
					241	0.0060	
					240	0.0084	
					239	0.0105	
					231	0.0180	
					227	0.0264	
					225	0.0170	
					222	0.0234	
					221	0.0087	
					120	0.0009	
					121	0.0195	
					128	0.0087	
					127	0.0090	
					126	0.0258	

1	2	3	4	1	2	3	4
		हेक्टेयर				हेक्टेयर	
					122	0.0078	
					114	0.0288	
					112	0.0228	
					111	0.0670	
	43	0.1040	6(2) चकमार्ग		46	0.0216	
					44	0.0150	
					48	0.0072	
					40	0.0075	
					39	0.0168	
					35	0.0096	
					34	0.0060	
					27	0.0090	
					33	0.0102	
					23	0.0045	
योग..	03 कित्ता	0.5684		योग..		0.5695	

(1) ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है तथा इस हेतु श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य स्थितियों में किया जा रहा है। संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भूमियों पर यदि कोई जन शिकायत अथवा वाद लम्बित हो तो उसके निस्तारण पश्चात् ही भूमियों के विनिमय संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त विनिमय के पश्चात् ग्रामवासियों के सुविधाजनक आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

दीपक मीणा,
जिलाधिकारी, मेरठ।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 03 सितम्बर, 2022 ई० (भाद्रपद 12, 1944 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क-नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख-नगर पंचायत,
खण्ड-ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ-जिला पंचायत।

खण्ड-घ-जिला पंचायत

जिला पंचायत, देवरिया

17 अगस्त, 2022 ई०

सं०-RII-169/तेईस-7 (2021-22)-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (1) एवं धारा 239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत देवरिया ने ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियां बनायी है। आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242(2) में दी गयी शक्ति का प्रयोग कर पुष्टि किये जाने के उपरान्त राजपत्र (गज़ट) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा। इन उपविधियों के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से संबंधित पूर्व प्रचलित उपविधियां निरस्त हो जायेंगी।

उपविधि

ये उपविधियां जिला पंचायत देवरिया के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जो कि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कम्पनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाऊसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन/परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी।

परिभाषाएँ—

1—अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

2—ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जनपद देवरिया में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3—विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4—मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाइन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जो कि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Elegible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5—निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6—भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मन्दी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7—छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जो कि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8—ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह, से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9—निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जो कि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10—तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खंड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11—फ्लोर एरिया रेशियो (FAR.) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलो के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12—भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भूतल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13—ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय प्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार, जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14—लेआउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जोकि किसी स्थल के समस्त भूखण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15—प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है:—

(अ) अभियंता-अभियंता, जिला पंचायत देवरिया से है।

(ब) अवर अभियंता-इस उपविधि में अवर अभियंता का तात्पर्य उस अवर अभियंता से है जिसको अभियंता, जिला पंचायत देवरिया द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निदेशित (Designated) किया गया हो।

16—कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत देवरिया से है।

17—अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18—स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19—रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

20—सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारो तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21—अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत देवरिया से है।

22—जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17(1) में संघटित जिला पंचायत देवरिया से है।

23—अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत देवरिया से है।

24—बहु मंजिली भवन (Multy Storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु मंजिल कहलायेगा।

25—मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके उपर कोई तल न हों, तो वह स्थान जो तल और इसके उपर की छत के मध्य हों।

26—भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जो कि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जायें, एवं उसका प्रत्येक भाग चाहें मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लैटफार्म, बरान्डा, बालकनी, कार्नास या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टेन्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जो कि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिये लगाये जाते हैं, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27—आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

28—व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29—संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसें पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-2 कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

30—भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31—पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चाहरदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

32—उपविधि द्वारा निर्धारित शुल्क सूची में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल पर जिला पंचायत द्वारा की जायेगी। जिस वित्तीय वर्ष में उपविधि लागू होगी, गणना हेतु वह पूर्ण वित्तीय वर्ष माना जायेगा। बढ़ोत्तरी की गणना करने पर जो धनराशि आयेगी, उसे दहाई के पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं हैं, का तात्पर्य वही होगा, जो कि ऐसे शब्दों का National building Code एवं Bureau of Indian standards यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभास की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां—

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा।

1—उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

अ—ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्ग मी0 क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होंगी परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत देवरिया को एक लिखित सूचना देनी होगी।

ब—सफेदी व रंग-रोशन के लिए।

स—प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए।

य—पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए।

र—प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण।

व—मिट्टी खोदने या मिट्टी से गढ़ा भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे—

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भू-खण्ड के लेआउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत देवरिया को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा।

1—स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगा:—

ले-आउट प्लान का पैमाना 1 : 500 होगा।

की-प्लान का पैमाना 1 : 1000 होगा।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1 : 100 होगा।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम।

समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी।

स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख।

2-प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा ।

अ-प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित ।

ब-नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नंबर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर ।

स-नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर ।

य-भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिये प्रार्थना-पत्र ।

र-भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन

ल-स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्सन, स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण ।

व-नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता ।

स-नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण ।

3-बहु मंजिली भवन (मल्टी स्टोरी) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी-

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी, अग्निसुरक्षा लिफ्ट अग्निअलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location) ।

निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ आदि ।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियाँ-

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि :-

अ-प्रस्तावित भवन-उपयोग अनुम्य भू-उपयोग से भिन्न है ।

ब-प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनायें आहत होती हों ।

स-प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनायें भड़काने का स्रोत (Source Of Annoyance) अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो ।

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)-

1-क-एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है ।

ख-भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊँचाई तक अनुमन्य होगी ।

ग-लिंगल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा ।

घ-बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा । बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मीटर होगी । स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लॉट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है ।

ड-बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा ।

च-राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊँचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात् प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जायेगी। भू-खण्ड के डैड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी।

छ-बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है। सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मीटर होगी।

2-निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिये भू-खण्ड का 10% क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है :-

क-जेनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राइवर रूम, विद्युत उप केन्द्र आदि।

ख-मस्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

ग-ढके हुए पैदल पथ आदि।

3-क-आवासीय भवन में कमरे का आकर 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

ख-छत की सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए।

ग-ऐंसी० कमरे की ऊँचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए।

घ-रसोईघर की ऊँचाई 2.75 मीटर, आकर 1.80 मीटर एवं 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

ङ-संयुक्त संडास (TOILET) का आकर 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

च-खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10% से कम न होना चाहिए।

छ-तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए !

4-क-पार्क, टोट-लोट्स (Tot-Lots), लैंड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15% होगा।

ख-30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रंट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी !

ग-भू-कम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।

5-स्वीकृत किये किये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा सवय की जायेगी जिला पंचायत का इसके लिए, कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

6-बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ङ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम-

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)—

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत होंगे :—

क्रमांक	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊँचाई (मीटर)
1	2	3	4	5
1	(i) आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15
	(ii) (i) आवासीय भवन भू-खण्ड 500—2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रेन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	12
4	व्यावसायिक भवन			
	(i) सुविधा (Convenient) शॉपिंग केन्द्र, शॉपिंग माल्स, व्यावसायिक केन्द्र, होटल	40	2.50	21
	(ii) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	18
	(iii) वेयरहाउस, गोदाम	60	1.50	15
	(iv) दुकाने व मार्केट	60	1.50	10
5	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन			
	(i) सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कॉलेज आदि	50	1.50	15
	(ii) हायर सेकंडरी, प्राइमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	15
	(iii) हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	15
6	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन	50	1.20	10
	(i) सामुदायिक केन्द्र क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	10
	(ii) धर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	40	2.50	10
	(iii) धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह	40	0.50	6
7	कार्यालय भवन			
	सरकारी, अर्धसरकारी, कॉर्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	15
8	क्रीड़ा एवं मनोरंजन कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रेंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	20	0.40	10
9	नर्सरी	10	0.50	6
10	बस स्टेशन, बस डिपों, कार्यशाला	30	2.00	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	6
12	डेरी फार्म	10	0.15	6
13	मुर्गा, सुअर, बकरी फार्म	20	0.30	6
14	ए०टी०एम०	100	1.00	6

(ज) सेट बेक (Set Back)–

क्रमांक	भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सामने (Front) मीटर	साईड (Side) मीटर	पीछे (Reer) मीटर	लैण्ड स्केपिंग (Land Scaping) मीटर	खुला स्थान % तक
1	2	3	4	5	6	7
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2	151–300	3.0	0.0	3.0	तदैव	25
3	301–500	4.5	3.0	3.0	तदैव	25
4	501–2000	6.0	3.0	3.0	तदैव	25
5	2001–6000	7.5	4.5	6.0	तदैव	25
6	6001–12000	9.0	6.0	6.0	तदैव	25
7	12001–20000	12.0	7.5	7.5	तदैव	50
8	20001–40000	15.0	9.0	9.0	तदैव	50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदैव	50

(झ) पार्किंग स्थान–

क्रमांक	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	2	3
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यावसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रुम के लिए
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासी भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

(ज) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसेस–

- (i)–तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा—संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन व्यावसायिक भवन हॉस्पिटल, नर्सिंग होम सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दिवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा। जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

- (ii)—अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 से०मी०, राईजर अधिकतम 19 से०मी०, एक फ्लाइंट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।
- (iii)—अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।
- (iv)—घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में नहीं किया जायेगा।
- (v)—उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।
- (vi)—उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे— स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति, फर्स्ट एंड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी—

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी मीटर	क्षैतिज दूरी मीटर
1	लो एंड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7 + (0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8 + (0.305 m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

(ठ) मोबाइल टावर की स्थापना—

- क—मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।
- ख—जनरेटर केवल 'साइलेंट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेंगे।
- ग—यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए।
- घ—जहाँ अपेक्षित हो, वहाँ टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- ङ—सेवा ऑपरेटर कंपनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बंधित कंपनी और भवन स्वामी का होगा।
- च—इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो विकिरण, वायुब्रेसन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा !
- छ—अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये प्रथम बार शुल्क के रूप में पचास हजार रुपये जिला पंचायत में जमा कराने होंगे। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यापणीय (Non-Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10% प्रति वर्ष जमा कराने होंगे।
- ज—शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

(ड) नक्शे स्वीकृति की दरें—

क—आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन :—

जनपद देवरिया में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर दर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

ख—व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन :—

जनपद देवरिया में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर दर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

ग—(i) भूमि की प्लॉटिंग—भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लॉटों में बाँटना।

(ii) भूमि विकास—भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि।

(iii) भूमि का उपभोग—भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे—निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईंधन आर०सी०सी० पाईप आदि।

(iv) किसी परियोजना का ले आउट प्लान (तलपट मानचित्र)

उपरोक्त ग— (i) से (iv) तक, जिला पंचायत में देवरिया में यह दर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

घ—पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी।

ङ—स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी।

च—बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की, अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

छ—यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10% होंगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50% होंगी।

ज—उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत, देवरिया से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने, अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20% से अधिकतम 50% अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गयी व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

झ—जनपद देवरिया में पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर होंगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी।

ण—जनपद देवरिया में बाउन्ड्री वाल स्वीकृति की दरें 5 रुपये प्रति मीटर होगी।

नोट—(शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)।

(ण) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया—

1—स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2—ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3—कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4—कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियंता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5—अभियंता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित (Designated) अवर अभियंता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6—अवर अभियंता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियंता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7—अवर अभियंता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यवसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियंता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8—अभियंता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियंता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शों के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध यह है, कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9—जिला पंचायत के अभियंता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility), सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदन कर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10—अभियंता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियंता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11—अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिये एक माह का समय दिया जायेगा।

12—आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13—उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14—यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग-पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवाद—उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को संदर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश अभयपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(त) सामान्य अनुदेश (General Instructions)–

1-भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.5 किलो मीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं ऊँचाई की अनुमति, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

2-भू-खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

3-भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भंडारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा तल (Service Floor) भंडारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाये तो इनका क्षेत्रफल एफ०ए०आर० में शामिल नहीं होगा।

4-निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तन प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो, के 5 किमी० की परिधि में 30 मी० से ऊँचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5-उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो, कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, प्लोर एरिया रेशियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6-उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा, इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7-मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।

8-इन उपविधियों के अधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9-इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी०आर०पी०सी० की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(थ) अनुज्ञा की शर्तें–

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये कि नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (seal) किया जा सकता है।

क-अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा की वह, अभियंता जिला पंचायत की संस्तुति पर, वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकृत कर दे।

ख-पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद के अंतर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियंता द्वारा कराया जायेगा।

ग-कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत देवरिया से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत देवरिया यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन रु० 1,000 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो सके कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु० 50 प्रतिदिन हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास से दण्डित किया जायेगा जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

बालेश्वरी देवी,
अध्यक्ष,
जिला पंचायत, देवरिया।

खण्ड-घ जिला पंचायत

18 अगस्त, 2022 ई०

उपविधि/संशोधन सूचना

सं० 2581/विकास सहायक/2022-23-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 239(1) एवं 239(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, मैनपुरी में प्रचलित उपविधि संख्या-2052/इक्कीस-7(1)-91-92 गजट दिनांक 19 नवम्बर, 1994 में वर्णित धारा 12 व प्रचलित उपविधि संख्या-508/इक्कीस-7-(4)-(72-73) गजट दिनांक 06 मार्च, 1993 में वर्णित धारा 8 एवं 13 में संशोधन/परिवर्धन किया गया है। पंचायतीराज अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या 1152/33-2-217-62जी/2017 दिनांक 04 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रचलित उपविधियों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से मानक उपविधि जारी की गई है, के अनुपालन में उपरोक्त वर्णित प्रचलित उपविधियों में संशोधन/परिवर्धन किया गया है, जिसका अनुमोदन जिला पंचायत बोर्ड बैठक दिनांक 08.01.2021 के प्रस्ताव संख्या 4 द्वारा पारित किया गया है। पारित प्रस्ताव के क्रम में दैनिक समाचार-पत्र आज के अंक दिनांक 18.07.2019 एवं अंक 21.07.2019 भूल सुधार संशोधन एवं उपविधि संशोधन सूचना दैनिक जागरण के अंक 12.02.2021 एवं दैनिक आज के अंक 14.02.2021 में संशोधित उपविधि का प्रकाशन कराकर जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव 30 दिन के अन्तर्गत मांगे गये निर्धारित अवधि तक सुझाव/आपत्ति कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। संशोधित/परिवर्धित उपविधि उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 242(2) के अनुसार आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा के अनुमोदन/स्वीकृति के पश्चात् शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

उपनियम

- 1-यह उपविधि जिला पंचायत, मैनपुरी के ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के उद्योगों से लाईसेंस शुल्क से सम्बन्धित उपविधि कहलायेगी।
- 2-यह उपविधि जिला पंचायत, मैनपुरी के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान और भविष्य में स्थापित होने वाले एवं वर्तमान में चलने वाले विभिन्न प्रकार के उद्योगों को नियंत्रित करेगी।
- 3-चिमनी ईट भट्टा लाईसेंस की अवधि 01 अक्टूबर से 30 सितम्बर तक होगी।
- 4-01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक नवीनीकरण न कराने पर मु०: रू० 5,000.00 विलम्ब शुल्क जमा करना होगा, उसके उपरान्त लाईसेंस न लेने पर चिमनी ईट भट्टा मालिक के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।
- 5-चिमनी ईट भट्टा को छोड़कर विभिन्न प्रकार के अन्य उद्योगों की लाईसेंस अवधि एक वर्ष की होगी, जो दिनांक 01 अप्रैल से प्रारम्भ होगी एवं 31 मार्च को समाप्त होगी। दिनांक 30 जून तक लाईसेंस नवीनीकरण न कराने पर 25 प्रतिशत (नियत लाईसेंस शुल्क के अतिरिक्त) विलम्ब शुल्क देय होगा।
- 6-फैक्ट्री, कारखाना, प्लान्ट आदि जो विज्ञप्ति संख्या-2552/इक्कीस-7(1)-9192 दिनांक 19 नवम्बर, 1994 तथा चिमनी ईट भट्टा आदि 06 मार्च, 1993 को राजकीय गजट में प्रकाशित हैं, में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परिभाषायें एवं उपनियम यथावत् लागू रहेंगे।
- 7-फैक्ट्री, कारखाना, चिमनी ईट भट्टा आदि की लाईसेंस शुल्क की संशोधित दरों का विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	मद/व्यवसाय/कारखाने का नाम	पूर्व दरें	संशोधित दरें
1	2	3	4
			रू०
1	चीनी मिल	-	50,000.00
2	क्रेसर हाईड्रॉलिक सल्फीटेशन	-	4,000.00
3	क्रेसर नॉन हाईड्रॉलिक सल्फीटेशन	-	4,000.00
4	क्रेसर नॉन हाईड्रॉलिक नॉन सल्फीटेशन	-	2,500.00
5	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	-	400.00

1	2	3	4
			रु0
6	शक्ति चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	-	1,000.00
7	हस्तचालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	-	200.00
8	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर	-	300.00
9	धान कूटने का राइस सेलर	300.00	2,500.00
10	एक्सपेलर	300.00	500.00
11	आरा मशीन	500.00	2,000.00
12	खराद मशीन	300.00	1,000.00
13	पावर लूम (प्रत्येक)	300.00	1,000.00
14	रेशम व कपड़ा बनाने का कारखाना	-	4,000.00
15	सरिया बनाने का कारखाना	-	15,000.00
16	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्टी)	-	5,000.00
17	वर्फ बनाने का कारखाना (200 सिल्ली तक)	500.00	2,000.00
18	वर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)	500.00	4,000.00
19	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	-	7,000.00
20	पेपरकॉन बनाने का कारखाना	-	4,000.00
21	पेपररोल बनाने का कारखाना	-	8,000.00
22	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता)	1,000.00	10,000.00
23	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक 20 टन क्षमता तक)	1,000.00	15,000.00
24	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन क्षमता तक)	1,000.00	30,000.00
25	कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता से अधिक)	1,000.00	50,000.00
26	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	-	10,000.00
27	चिलिंग प्लान्ट	-	8,000.00
28	स्टील आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2 इन्च मोटाई तक)	-	25,000.00
29	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2 इन्च मोटाई से अधिक)	-	50,000.00
30	मशीन यन्त्र बनाने का कारखाना	-	7,000.00
31	फल सब्जियाँ एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग तक)	2,500.00	10,000.00
32	फल सब्जियाँ एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग से अधिक क्षमता तक)	2,500.00	15,000.00
33	पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना	-	5,000.00
34	हॉटमिक्स प्लान्ट	-	10,000.00
35	रबड़ की वस्तुयें बनाने का कारखाना	-	2,000.00

1	2	3	4
			रु०
36	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल बनाने का छोटा कारखाना	-	2,000.00
37	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल बनाने का बड़ा कारखाना	-	7,000.00
38	मसाले की ईंट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	-	8,000.00
39	पीतल, अल्मोनियम, स्टील, शीशा, तौबा व टीन आदि वस्तुयें बनाना	-	4,000.00
40	वनस्पति/देशी घी या रिफाइण्ड ऑयल बनाने का कारखाना	-	15,000.00
41	शराब, स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	-	50,000.00
42	कृषि सम्बन्धी यन्त्र बनाने का कारखाना	-	4,000.00
43	फटिलाइजर्स या कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना	-	10,000.00
44	खाण्डसारी उद्योग के यन्त्र बनाने का कारखाना	-	5,000.00
45	प्लास्टिक का दाना/फिल्म या बैग बनाने का कारखाना	-	4,000.00
46	प्लास्टिक के पाईप, टैंक बनाने का कारखाना	-	7,000.00
47	बिजली के सामान बनाने का कारखाना	-	4,000.00
48	कपड़ा कम्बल आदि की रंगाई, छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (छोटा)	-	2,000.00
49	कपड़ा कम्बल आदि की रंगाई, छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (बड़ा)	-	8,000.00
50	सीमेन्ट बनाने का कारखाना	-	10,000.00
51	फ्लोर मिल	2,000.00	10,000.00
52	दाल मिल	500.00	5,000.00
53	रिईनफोर्सड, सीमेन्ट, कन्क्रीट आदि के ह्यूम पाइप बनाने का कारखाना	-	10,000.00
54	टेलीविजन बनाने का कारखाना	-	10,000.00
55	माचिस बनाने का कारखाना	-	10,000.00
56	बटन बनाने का कारखाना	-	6,000.00
57	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	-	3,000.00
58	विनियर एण्ड शॉ मिल	-	7,000.00
59	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	-	50,000.00
60	मिनरल वॉटर बनाने का कारखाना	-	15,000.00
61	साफिट बनाने का कारखाना	-	5,000.00
62	प्लार्डबुड या माईका बनाने का कारखाना	1,000.00	10,000.00
63	दवाई बनाने का कारखाना	2,000.00	7,000.00
64	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	-	3,000.00
65	लेमिनेशन का कारखाना	-	5,000.00
66	दूध पैकिजिंग का कारखाना	-	6,000.00
67	कैमिकल बनाने का कारखाना	-	8,000.00

1	2	3	4
			रु0
68	डबल रोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना	-	5,000.00
69	गैस आदि बनाने का कारखाना	-	5,000.00
70	गैस के सिलिण्डर बनाने का कारखाना	-	8,000.00
71	वैल्विंग रॉड बनाने का कारखाना	-	6,000.00
72	पीतल की रॉड्स बनाने का कारखाना	-	6,000.00
73	ढलाई करने का कारखाना	-	6,000.00
74	स्टील अलमारी, बक्से, मेज आदि बनाने का कारखाना	-	6,000.00
75	पशुआहार बनाने का कारखाना	-	5,000.00
76	धागा बनाने का कारखाना	-	4,000.00
77	धागा डबलिंग का कारखाना	-	7,000.00
78	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना	-	7,000.00
79	साबुन बनाने का कारखाना	500.00	2,000.00
80	डिटेर्जेंट बनाने का कारखाना	-	7,000.00
81	पट्टा बनाने का कारखाना	-	3,000.00
82	कमानी पट्टा बनाने का कारखाना	-	7,000.00
83	रबड़ के टायर ट्यूब बनाने का कारखाना	-	15,000.00
84	टायर रिट्रेलिंग	-	4,000.00
85	तिरपाल बनाने का कारखाना	-	10,000.00
86	आतिशबाजी सम्बन्धी सामान बनाने का कारखाना	-	10,000.00
87	ग्रीश, मोबिल ऑयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना	-	5,000.00
88	चार पहिया वाहन बनाने का कारखाना	-	1,00,000.00
89	दो पहिया वाहन बनाने का कारखाना	-	50,000.00
90	तार बनाने का कारखाना	-	15,000.00
91	तार की जाली बनाने का कारखाना	-	3,500.00
92	लालटेन बनाने का कारखाना	-	3,000.00
93	रेगमान बनाने का कारखाना	-	4,000.00
94	बैटरी बनाने का कारखाना	-	5,000.00
95	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	-	5,000.00
96	रंग बनाने का कारखाना	-	5,000.00
97	गम, टेप बनाने का कारखाना	-	4,000.00
98	ऑटो मीटर्स बनाने का कारखाना	-	5,000.00
99	निकिल पॉलिस (प्लेटिंग) बनाने का कारखाना	-	5,000.00
100	रांगा बनाने का कारखाना	-	5,000.00

1	2	3	4
			रु0
101	गैस चूल्हा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	-	5,000.00
102	हड्डी मिल	-	25,000.00
103	सरेश मिल	-	5,000.00
104	पेट्रोल पम्प	-	4,000.00
105	डीजल पम्प	-	5,000.00
106	गैस बाटलिंग प्लान्ट	-	25,000.00
107	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	-	2,000.00
108	प्रिन्टिंग प्रेस या ऑफसेट प्रेस	-	2,500.00
109	सिनेमा हॉल	-	4,000.00
110	वीडियो सिनेमा हॉल	-	2,500.00
111	मुर्गा/मुर्गीदाना/मछली दाना का कारखाना/फैक्ट्री	-	3,000.00
112	पेट्रोल पम्प या टैंक बनाने का कारखाना	-	10,000.00
113	रेडीमेड गारमेण्ट का कारखाना	-	15,000.00
114	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना	-	15,000.00
115	स्लाटर हाउस/इन्टीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लान्ट	-	100,000.00
116	ट्रान्सफॉर्मर फैक्ट्री	-	20,000.00
117	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना	-	15,000.00
118	एयर कन्डीशनर बनाने का कारखाना	-	10,000.00
119	जूट, सन व नाइलॉन बनाने का कारखाना	-	5,000.00
120	शीशा बनाने का कारखाना	-	3,000.00
121	पिपरमेन्ट बनाने का कारखाना	-	2,000.00
122	चमड़ा टेनरी का कारखाना	-	25,000.00
123	जैबिक कारखाना	-	5,000.00
124	फिक्स चिमनी ईट भट्टा (20 पाये तक)	2,000.00	10,000.00
125	फिक्स चिमनी ईट भट्टा (20 पाये से अधिक)	2,000.00	15,000.00
126	स्टोन क्रेसर	-	15,000.00
127	राईस मिल	2,000.00	20,000.00
128	अन्य व्यवसाय, गोदाम/वेयर हाउस/मैनेजमेन्ट कॉलेज	-	10,000.00
129	बैंकट हॉल/मैरिज होम	-	10,000.00
130	सूक्ष्म/कुटीर उद्योग (माईक्रो)(लागत 25,00,000.00 तक)	1,000.00	5,000.00
131	लघु उद्योग (स्मॉल)(25,00,000.00 से 5,00,00,000.00 तक)	1,000.00	20,000.00
132	मध्यम उद्योग (मीडियम)(लागत 5 करोड़ से 10 करोड़ तक)	-	50,000.00
133	भारी उद्योग (हैवी)	2,000.00	100,000.00

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 240 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, मैनपुरी निर्देश देती है कि उपरोक्त किसी भी उपविधि का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर अंकन रू0 1,000.00 (एक हजार रुपया) का अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद प्रत्येक ऐसे दिवस के लिये जिसमें उल्लंघन जारी रहा है तो अंकन रू0 50.00 (पचास रुपये) प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड दिया जा सकता है और अर्थदण्ड जमा न करने पर तीन मास का कारावास का भी दण्ड दिया जा सकता है।

अमित गुप्ता,
आयुक्त,
आगरा मण्डल, आगरा।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 03 सितम्बर, 2022 ई० (भाद्रपद 12, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

सूचना

मैं रिशुतोष सिंह पुत्र अरविन्द सिंह हाई स्कूल सी०बी०एस०सी० बोर्ड का अंक प्रमाण-पत्र अनुक्रमांक 5052896 वर्ष 2016 में मेरी माता का नाम श्यामा सिंह के जगह पर सीमा सिंह अंकित हो गया है। उनका सही नाम श्यामा सिंह है। ग्राम व पो०.पहुँची उर्फ मदनही, जिला गाजीपुर उ०प्र० है।

रिशुतोष सिंह।

सूचना

मेरा नाम विजय शंकर दूबे है एवं समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम विजय शंकर दूबे है। त्रुटिवश मेरी सेवा पुस्तिका में विजय शंकर दूबे की जगह विजय शंकर अंकित है। उपर्युक्त दोनों नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे विजय शंकर दूबे पुत्र बेनी प्रसाद दूबे के नाम से जाना व पहचाना जाए।

विजय शंकर दुबे,
59, कच्ची सड़क,
दारागंज, प्रयागराज।

सूचना

सूचित किया जाता है कि SBI Mutal Fund के फोलियो सं०-11476206 में त्रुटिवश मेरे नाबालिग पुत्र का घरेलू/पुकारने का नाम TAARAN GANESH अंकित हो गया है यद्यपि उसे अन्य अभिलेखों आधार पैन, विद्यालय में उसका नाम REVANT SRIVASTAVA अंकित है। चूंकि TAARAN GANESH और REVANT SRIVASTAVA दोनों एक ही व्यक्ति है। अतः भविष्य में इन्हें TAARAN GANESH के स्थान पर REVANT SRIVASTAVA के नाम से जाना व पहचाना जाये।

शालिनी श्रीवास्तव।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म VASTECH GROUP, 3/12, Usmanpur Colony, Juhi, Kanpur Nagar 208014 के विधान में भागीदारी डीड दिनांक 27 जुलाई, 2022 से फर्म की साझीदारी से साझीदार श्री सौरभ कुमार वर्मा पुत्र स्व० लक्ष्मी नारायण वर्मा निवासी डी-76, न्यू आवास विकास कालोनी, कानपुर रोड, झाँसी, उ०प्र० 204003 तथा वर्तमान स्थायी पता मकान

नं0-2, प्रथम तल, स्ट्रीट नं0-1, शीतला इन्क्लेव, फेस-3, गुड़गाँव-122001, हरियाणा (भारत) स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। वर्तमान में फर्म में श्री विशाल वर्मा एवं श्री अंकुर श्रीवास्तव साझीदार हैं।

विशाल वर्मा,
पार्टनर

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 श्री बाँके बिहारी आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, इगलास रोड, सासनी जिला हाथरस-204216 के पूर्व भागीदार श्री संजय कुमार उपाध्याय पुत्र श्री राम गोपाल उपाध्याय निवासी गली नं0-3, टीचर्स कॉलोनी, सासनी जिला हाथरस एवं श्रीमती प्रगति वार्ष्णेय पत्नी श्री राजीव कुमार वार्ष्णेय निवासी मोहल्ला अग्रवाल, सासनी जिला हाथरस उक्त फर्म से दिनांक 19 मई, 2022 से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं तथा श्रीमती विमलेश शर्मा पत्नी श्री प्रेम प्रकाश शर्मा निवासी एच0आई0जी0-10, पुष्पांजली, रामघाट रोड अलीगढ़ दिनांक 19 मई, 2022 से नई भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गयी हैं। अब फर्म में श्री देवेन्द्र कुमार अग्रवाल, श्री सुनील कुमार शर्मा व श्रीमती विमलेश ही भागीदार रह गये हैं।

देवेन्द्र कुमार अग्रवाल,
भागीदार,

मे0 श्री बाँके बिहारी आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, इगलास रोड, सासनी जिला हाथरस-204216

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे घर का नाम मो0 सलीम है। मेरे शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम मो0 मोहसिन (MD. MOHSIN) पुत्र नसीरुद्दीन है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 399112366228 में मेरे घर का नाम मो0 सलीम अंकित हो गया है। भविष्य में मुझे मो0 मोहसिन पुत्र नसीरुद्दीन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

मो0 मोहसिन

पुत्र नसीरुद्दीन पता-1238,
मालवीय नगर, कल्याणी देवी, प्रयागराज।

सूचना

मेरे भारतीय जीवन बीमा पालिसी सं0-310698664 में त्रुटिवश मेरा नाम (सुरेन्द्र कुमार सिंह) दर्ज है जो गलत है जबकि मेरे आधार व अन्य दस्तावेजों में मेरा सही नाम

सचिन कुमार सिंह दर्ज है सुरेन्द्र कुमार सिंह व सचिन कुमार सिंह दोनों नाम मेरे एक ही व्यक्ति के हैं। अतः सही नाम सचिन कुमार सिंह पुत्र श्री गनेशी लाल सिंह निवासी इरादतगंज घूरपुर तहसील बारा प्रयागराज के नाम से जाना पहचाना व दर्ज किया जाये।

सचिन कुमार सिंह,
पुत्र गनेशी लाल सिंह,
निवासी इरादतगंज, घूरपुर,
तहसील बारा, जनपद प्रयागराज।

सूचना

मेरे भारतीय जीवन बीमा पालिसी सं0-231206418 व 230994138 में त्रुटिवश मेरा नाम (मुनमुन) दर्ज है जो गलत है जबकि मेरे आधार व अन्य दस्तावेजों में मेरा सही नाम तनुषा दर्ज है मुनमुन व तनुषा दोनों नाम मेरे एक ही महिला के हैं। अतः सही नाम कु0 तनुषा पुत्री श्री महेन्द्र कुमार निवासी 785/442 चकरघुनाथ नैनी प0 अरैल तहसील करछना प्रयागराज के नाम से जाना पहचाना व दर्ज किया जाये।

कु0 तनुषा,
पुत्री श्री महेन्द्र कुमार,
निवासी 785/442 चकरघुनाथ नैनी
प0 अरैल, तहसील करछना,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

फर्म मेसर्स स्टिच क्राफ्ट खसरा नं0 1238 बाँईपुर अपोजिट सी0 एन0 जी0 पम्प आगरा मथुरा रोड सिकन्दरा आगरा पत्रावली संख्या एजीआर/0004564 में दिनांक 13 जनवरी, 2022 को जितेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री नेपाल सिंह निवासी-एल0आई0जी0-135 आवास विकास कालोनी, आगरा रोड, अलीगढ़ फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हुये दिनांक 13 जनवरी, 2022 को रवि मनचन्दा पुत्र स्व0 जयकृष्ण मनचन्दा निवासी-1, परिणय कुंज गेट नं0 2 बाग फरजाना आगरा फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुये वर्तमान फर्म में भागीदार शिवांक मनचन्दा, दीपक मनचन्दा, रवि मनचन्दा हैं।

शिवांक मनचन्दा,
साझेदार,
मे0 स्टिच क्राफ्ट

खसरा नं0 1238 बाँईपुर अपोजिट
सी0एन0जी0 पम्प आगरा मथुरा रोड,
सिकन्दरा आगरा।

NOTICE

I, hitherto known as O P TIWARI S/o CHATURBHUI TIWARI, residing at H. No. 543, PREM GANJ, SIPRI BAZAR, JHANSI, UTTAR PRADESH-284003, have changed my name and shall be known as OMPRAKASH TIWARI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

OMPRAKASH TIWARI.

सूचना

फर्म मेसर्स महर्षि दयानन्द आयरन फाउण्ड्री 71 इण्डस्ट्रीयल एस्टेट नुनिहाई आगरा पत्रावली संख्या एजीआर/11313 में दिनांक 09 मार्च, 2022 को श्री मुकेश चन्द बंसल पुत्र स्व0 प्रभूदयाल बंसल निवासी-ई-229 कमला नगर आगरा के निधन होने के उपरान्त पुर्नगठित साझेदारी विलेख दिनांक 14 मार्च, 2022 को श्री आर्यन बंसल पुत्र श्री अमित बंसल निवासी-ई-229 कमला नगर आगरा फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हुये तद्दिनांक को मनीष अग्रवाल पुत्र श्री राम प्रकाश अग्रवाल निवासी-88 यमुनोत्री बिहार कर्मयोगी कमला नगर आगरा व राजीव अग्रवाल पुत्र श्री भगवान दास अग्रवाल निवासी-ए-696 कमला नगर आगरा तथा दर्पण अग्रवाल पुत्र श्री पंकज अग्रवाल निवासी-7 वैभव एन्क्लेव फेस-1 कमला नगर आगरा फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुये, वर्तमान फर्म में साझेदार मनीष अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, दर्पण अग्रवाल, अमित बंसल हैं।

मनीष अग्रवाल,
साझेदार,

मेसर्स-महर्षि दयानन्द आयरन फाउण्ड्री,
71 इण्डस्ट्रीयल एस्टेट नुनिहाई आगरा।

सूचना

फर्म मे0 टॉप लास्ट्स खसरा नं0 1261, 1262, 1263, 1264, 1266 मौजा बॉईपुर 7.8 कि0मी0 आगरा मथुरा रोड अपोजिट हायडल सब स्टेशन सिकन्दरा आगरा पत्रावली संख्या एजी0-6481 में दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को जय कृष्ण मनचन्दा (एच0यू0एफ0) पुत्र श्री रामदास मनचन्दा निवासी-13/112 चार बाग शाहगंज आगरा एवं दीपक मनचन्दा (एच0यू0एफ0) पुत्र स्व0 कैप्टन जयकृष्ण मनचन्दा निवासी-13/112 चार बाग शाहगंज आगरा फर्म

की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हुये दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को शिवांक मनचन्दा पुत्र श्री रवि मनचन्दा निवासी-1, परिणय कुंज गेट नं0 2 बाग फरजाना आगरा एवं मनन मनचन्दा पुत्र श्री दीपक मनचन्दा निवासी-13-14 प्रोप0 1/149 काले का ताल देहली गेट आगरा एवं दीपक मनचन्दा पुत्र स्व0 कैप्टन जयकृष्ण मनचन्दा निवासी-13-14 प्रोप0 1/149 काले का ताल देहली गेट आगरा फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुये वर्तमान फर्म में भागीदार दीपक मनचन्दा, रवि मनचन्दा, शिवांक मनचन्दा, मनन मनचन्दा हैं तथा फर्म का पता दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से परिवर्तित कर खसरा नं0 1261, 1262, 1263, 1264, 1266 मौजा बॉईपुर 7.8 कि0मी0 आगरा मथुरा रोड अपोजिट हायडल सब स्टेशन सिकन्दरा आगरा कर लिया गया है।

दीपक मनचन्दा,

साझेदार,

मे0 टॉप लास्ट्स, खसरा नं0
1261, 1262, 1263, 1264, 1266
मौजा बॉईपुर 7.8 कि0मी0 आगरा
मथुरा रोड अपोजिट हायडल सब
स्टेशन सिकन्दरा आगरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेसर्स जी0जे0 कॉन्ट्रक्टर्स एण्ड सप्लायर्स, निकट गांधी पार्क मार्केट नूरपुर रोड, बिजनौर (यू0पी0) जिसकी पंजीकरण सं0-BIJ/0002724 है। उक्त फर्म के पंजीकरण के समय फर्म में तीन पार्टनर नवनीत सिंह, अनूप कुमार एवं साजिद अली खान थे। पार्टनर साजिद अली खान ने दिनांक 24 अगस्त, 2022 को त्याग-पत्र/रिटायरमेन्ट लेकर अपनी साझेदारी समाप्त कर ली है। जिनके स्थान पर दिनांक 26 अगस्त, 2022 को श्री अभिनय कुमार शामिल हो गये हैं। त्याग-पत्र/रिटायरमेन्ट लेने वाले पार्टनर की फर्म पर अब कोई लेनदारी/देनदारी नहीं है। उक्त फर्म में अब वर्तमान में तीन पार्टनर, पार्टनर नवनीत सिंह, अनूप कुमार एवं अभिनय कुमार हैं।

नवनीत सिंह,

मेसर्स जी0जे0 कॉन्ट्रक्टर्स एण्ड सप्लायर्स,
निकट गांधी पार्क मार्केट नूरपुर रोड,
बिजनौर (यू0पी0)

सूचना

सर्वविदित हो कि मैं मनोज कुमार यादव (MANOJ KUMAR YADAV) आर्मी नं0 JC 289819N. NB/SUB (OPR) पुत्र स्व0 परशुराम यादव ग्राम बैरिया पो चेरुइयां (फेफना) बलिया उ0प्र0 पिन 277503 यह कि मेरे सरकारी अभिलेख में मेरे नाम YADAW में स्पेलिंग त्रुटिवश गलत दर्ज हो गया है, जबकि सही स्पेलिंग YADAV है।

मनोज कुमार यादव।

NOTICE

I, hitherto known as RJESH PETARI S/o Sri Guru Bakash Pethari Residing at 423, Type 2, Sector 1, Township BHEL, Jhansi BHEL, Uttar Pradesh-284120 have changed my name and shall hereafter be know as RAJESH PETHARI.

It is certified that I have complied with other lagal requirements in this connection.

RJESH PETARI.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स रमेश गारमेन्ट्स, शॉप नं0-11, एच-362, सेक्टर-22, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर-201301 की दिनांक 11 जनवरी, 2018 की साझेदारी के अनुसार श्री रमेश चन्द्र लोहानी, श्री दीपक कुमार, श्रीमती रेनू लोहानी एवं श्रीमती नीतू कुमारी साझीदार थे। दिनांक 24 अगस्त, 2022 को श्री रमेश चन्द्र लोहानी, श्रीमती रेनू लोहानी एवं श्रीमती नीतू कुमारी साझीदार आपसी सहमति से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये हैं। फर्म अब वर्तमान में श्री दीपक कुमार की प्रोपराईटरशिप में संचालित होगी। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

दीपक कुमार,
साझीदार,

मेसर्स रमेश गारमेन्ट्स, शॉप नं0-11,
एच-362, सेक्टर-22, नोएडा,
जिला-गौतमबुद्धनगर-201301।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स गोयल पेन्ट्स एण्ड टाईल्स शोपी, एच-87, सेक्टर-9, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर की साझीदारी में श्री पंकज गोयल, श्रीमती रितु गोयल उर्फ रीतु गुप्ता, मेसर्स पंकज गोयल (एच0यू0एफ0), श्री प्रवीन कुमार एवं श्रीमती मधु गुप्ता साझीदार थे। दिनांक 05 सितम्बर, 2008 को श्री प्रवीन कुमार एवं श्रीमती मधु गुप्ता फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को फर्म की साझीदारी में श्री सोम्य गोयल सम्मिलित हुए हैं तथा मेसर्स पंकज गोयल (एच0यू0एफ0) अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गयी हैं। वर्तमान में संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार फर्म में श्री पंकज गोयल, श्रीमती रितु गोयल एवं श्री सोम्य गोयल साझीदार हैं। दिनांक 05 सितम्बर, 2008 के अनुसार फर्म का पता बी-1/19, सेक्टर-50, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर एवं शाखा कार्यालय एच-87, सेक्टर-9, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2018 के अनुसार फर्म का पता जी-104, सेक्टर-9, नोएडा जिला-गौतमबुद्धनगर एवं शाखा कार्यालय आई-11, बेसमेन्ट, सेक्टर-9, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर एवं साझीदार श्री पंकज गोयल एवं श्रीमती रितु गोयल जी का निवास बी0-53, सेक्टर-50, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर हो गया है।

पंकज गोयल,

साझीदार,

मेसर्स गोयल पेन्ट्स एण्ड टाईल्स शोपी,
जी-104, सेक्टर-9, नोएडा,
जिला-गौतमबुद्धनगर-201301।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 आर0एस0 कन्स्ट्रक्शन, 47 गोकुल धाम कालोनी बैराज रोड, औरंगाबाद, मथुरा में स्थित है एजी 8737 उपरोक्त फर्म में साझेदार राम जी लाल शर्मा पुत्र श्री मलखान शर्मा, अशोक कुमार पुत्र स्व0 रोशन लाल, श्री राकेश वर्मा पुत्र स्व0 रोशन लाल सभी साझेदारों ने अपनी संशोधित फर्म दिनांक 08 जनवरी, 2018 को संचालन की थी आज दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को श्रीमती राधा पत्नी स्व0 शिव राज सिंह, श्री प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री मलखान शर्मा नये साझेदार सम्मिलित हो गये हैं श्री रामजी लाल शर्मा

पुत्र श्री मलखान सिंह, राकेश वर्मा पुत्र श्री रोशन लाल भागीदारी फर्म से अलग हो गये हैं अब फर्म को अशोक कुमार, श्रीमती राधा, श्री प्रमोद कुमार शर्मा संचालित करेंगे।

अशोक कुमार,
साझेदार,
मेसर्स आर0एस0 कन्स्ट्रक्शन,
47 गोकुल धाम कालोनी बैराज रोड,
औरंगाबाद, मथुरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जे0आर0 हॉस्पिटल पता एन0एच0 07 बी ब्लॉक सेक्टर बीटा 1 ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश की पार्टनर्स शिप दिनांक 11 सितम्बर, 2009 को हुई थी संशोधित साझेदारीनामा दिनांक 28 फरवरी, 2017 के अनुसार जिसमें क्रमशः तीन साझेदार थे। 1 श्री जितेन्द्र पाल सिंह, 2 श्रीमती रेखा सिंह, 3 श्रीमती नीलिमा दीपक थे संशोधित साझेदारीनामा डीड दिनांक 16 मई, 2022 के अनुसार श्रीमती नीलिमा दीपक स्वेच्छा से इस फर्म से अलग हो गई हैं। अब इनका इस फर्म से कोई लेना-देना बकाया नहीं है अब इस फर्म में दो नये साझेदार मेसर्स सुत्रा मार्केटिंग एण्ड इवेन्ट्स एलएलपी की तरफ से श्री अर्निबान सैन और मेसर्स असगरी मेडिकल सर्विसीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से सबा नये साझेदार आये हैं तथा अब इस फर्म में क्रमशः चार साझेदार हो गये हैं। 1 श्री जितेन्द्र पाल सिंह, 2 श्रीमती रेखा सिंह, 3 मेसर्स सुत्रा मार्केटिंग एण्ड इवेन्ट्स एलएलपी, 4 मेसर्स असगरी मेडिकल सर्विसीज प्राइवेट लिमिटेड साझेदार हो गये हैं।

जितेन्द्र पाल सिंह,
साझेदार,
मेसर्स जे0आर0हॉस्पिटल,
एन0एच0 07 बी ब्लॉक सेक्टर बीटा 1,
ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

फर्म मे0 श्री बालाजी कृषि फार्म राजधानी काम्प्लेक्स पुराना हाथरस अड्डा आगरा रोड, अलीगढ़ पत्रावली संख्या एजी-12178 में दिनांक 01 जुलाई, 2022 को श्री नरेन्द्र कुमार माहेश्वरी पुत्र श्री रामकिशन माहेश्वरी

दुर्गा नगर आगरा रोड अलीगढ़ अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक हुये तददिनांक को श्रीमती छाया माहेश्वरी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार माहेश्वरी निवासी-बिहान्ड सिद्धार्थ बेन्कट हॉल दुर्गापुरी आगरा रोड, अलीगढ़ फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुई। वर्तमान फर्म में साझेदार श्री तेजवीर सिंह, दिव्यांश इन्फ्रा बिल्ड प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर अंकुर माहेश्वरी, श्रीमती अलका शर्मा, श्री विष्णु गोपाल, श्रीमती छाया माहेश्वरी हैं।

तेजवीर सिंह,
साझेदार,
मे0 श्री बालाजी कृषि फार्म,
राजधानी काम्प्लेक्स पुराना हाथरस अड्डा,
आगरा रोड, अलीगढ़।

सूचना

फर्म मे0 श्री राम कोलोनाइजर्स नेहरू कुंज मालीपाड़ा अलीगढ़ पत्रावली संख्या एजी/8652 में दिनांक 01 अप्रैल, 2012 को श्री जितिन गर्ग (एच0यू0एफ0) पुत्र श्री पवन कुमार गर्ग निवासी-बी-दास कम्पाउण्ड नौरंगाबाद, अलीगढ़ एवं तेजवीर सिंह पुत्र श्री कुँवरपाल सिंह निवासी-19/3-ए, दुर्गानगर, अलीगढ़ तथा दिनांक 27 नवम्बर, 2021 को निदेशक श्री नरेन्द्र कुमार माहेश्वरी (श्री बालाजी आवास विकास प्रा0लि0) पुत्र श्री रामकिशन माहेश्वरी निवासी-दुर्गा नगर सासनी गेट सिद्धार्थ लॉज कोल, अलीगढ़ एवं दिनांक 08 जुलाई, 2022 को श्रीमती छाया माहेश्वरी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार माहेश्वरी निवासी-बिहान्ड सिद्धार्थ बैंकट हॉल दुर्गापुरी आगरा रोड, अलीगढ़ को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है दिनांक 08 जुलाई, 2022 को नरेन्द्र कुमार माहेश्वरी पुत्र स्व0 आर0 के0 माहेश्वरी दुर्गा नगर सासनी गेट, अलीगढ़ फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हुये। वर्तमान में फर्म में साझेदार श्रीमती छाया गर्ग, श्री पुनीत गर्ग, श्रीमती राज कुमारी, श्री सतीश चन्द्र गर्ग, श्रीमती छाया माहेश्वरी, श्री अंकुर माहेश्वरी, जितिन गर्ग, तेजवीर सिंह, निदेशक, श्रीमती छाया माहेश्वरी श्री बालाजी आवास विकास प्रा0 लि0 हैं।

श्रीमती छाया गर्ग,
मे0 श्री राम कोलोनाइजर्स,
नेहरू कुंज मालीपाड़ा, अलीगढ़।

सूचना

फर्म मे० जनरल ट्रडर्स ए-10 इण्डस्ट्रीयल स्टेट आगरा रोड, फिरोजाबाद पत्रावली संख्या एजी-14071 में दिनांक 31 मार्च, 2022 को श्रीमती मंजू अग्रवाल पत्नी स्व० राज कुमार अग्रवाल निवासी-24 एस०एन० रोड फिरोजाबाद, श्री रजत अग्रवाल पुत्र श्री राज कुमार अग्रवाल निवासी-24 एस०एन०, रोड फिरोजाबाद, श्री भरत अग्रवाल पुत्र स्व० राजकुमार अग्रवाल निवासी-24 एस०एन० रोड फिरोजाबाद, श्रीमती मनोरमा रानी पत्नी स्व० सत्य नारायण जी अग्रवाल निवासी-24 एस०एन० रोड, फिरोजाबाद अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक हुये तद्दिनांक को श्री भगवान दास अग्रवाल पुत्र स्व० घूरे लाल अग्रवाल निवासी-71 जैन नगर खेड़ा,

फिरोजाबाद, श्री मुनेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० घूरेलाल अग्रवाल निवासी-70 जैन नगर खेड़ा, फिरोजाबाद, श्री विवेक अग्रवाल पुत्र श्री भगवान दास अग्रवाल निवासी-71 जैन नगर खेड़ा फिरोजाबाद, श्री नितिन बंसल पुत्र श्री मुनेन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी-70 जैन नगर खेड़ा, फिरोजाबाद फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुये, वर्तमान फर्म में भागीदार श्री भगवान दास अग्रवाल, श्री मुनेन्द्र कुमार अग्रवाल, श्री विवेक अग्रवाल, श्री नितिन बंसल, श्री संजय अग्रवाल हैं।

भगवान दास अग्रवाल,
साझेदार,
मे० जनरल ट्रडर्स,
ए-10 इण्डस्ट्रीयल स्टेट आगरा रोड, फिरोजाबाद।